फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 42 प्रभात जयपुर, शनिवार 12 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Traffic Jam In The Mughal Empire

Food had to move, and the Banjaras knew how, their importance was so great that rulers had powerful incentives to maintain relationships with caravan leaders

The Baker Who Pretended to Be Heartless

मोदी-पुतिन मुलाकात: कोई बड़ी शस्त्रों की खरीद फरोख्त नहीं पर संबंधों में मोमैन्टम बना रहा

ऐसा लगा, मोदी-पुतिन मुलाकात का मकसद सुरक्षा संबंधों में निरंतरता बनाए रखना है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नई दिल्ली में हुई मुलाकात ने भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की गहराई और मजबूती को और बढ़ाया है, लेकिन इसमें हथियारों की खरीद का कोई बड़ा नया समझौता नहीं हुआ है। हालांकि, बातचीत में डिफैंस का मुद्दा प्रमुख रूप से शामिल रहा, लेकिन रूस की उन्नत हथियार प्रणालियों, जिसमें एसयू-57 लड़ाकू विमान और अतिरिक्त एस-400 वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हैं, से जुड़े बहुप्रतीक्षित सौदे अभी भी सिर्फ प्रस्ताव या बातचीत के दौर में ही हैं।

- भारत की मंशा, भारत के पास जो रूसी हथियार हैं, उनकी सप्लाई बरकरार रखना, रख रखाव जारी रखना, उसको "अपग्रेड" करना तथा सपोर्ट सिस्टम चुस्त व तंदरूस्त रखना।
- दूसरे शब्दों में, पुतिन-मोदी मुलाकात से दोनों देशों के आपसी संबंधों को और दृढ़ व मजबूत करना।
- पुतिन द्वारा मोदी को 24वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में आने का न्यौता देना और मोदी द्वारा न्यौता तुरंत स्वीकार करना, पक्के रिश्तों का एक बड़ा प्रमाण है।

दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इसमें रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, परमाणु ऊर्जा सहयोग, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, इस्पात, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिज, सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरे। बातचीत से यह संकेत मिला कि दोनों देश रक्षा और तेल-गैस पर पारंपरिक निर्भरता से आगे बढ़कर संबंधों को अधिक विविध आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

डिफैंस से जुड़ा सबसे अधिक चर्चा का मुद्दा रूस का एसयू-57 पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जैट का प्रस्ताव था। बताया जाता है कि मॉस्को ने भारत को इस विमान के दो स्क्वाड्रन देने और इसके अलावा अन्य स्क्वाड्रनों का भारत में ही उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ तकनीक हस्तांतरण की भी पेशकश की गई है। ऐसी व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन और तकनीक हासिल करने पर बढ़ते जोर के अनुरूप होगी। हालांकि, मोदी-पुतिन मुलाकात के दौरान एसयू-57 खरीद समझौते की घोषणा नहीं की गई।

एस-400 एयर डिफैंस सिस्टम भी भारत-रूस रक्षा संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। भारत रूस से एस-400 प्रणालियां पहले ही खरीद चुका है और अतिरिक्त प्रणालियों तथा मिसाइलों की आपूर्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, हाल की मुलाकात के दौरान किसी नए बड़े एस-400 समझौते की घोषणा नहीं हुई। ऐसा लगता है कि जोर इस बात पर है कि भारत के पास मौजूद रूस निर्मित सैन्य उपकरणों के लिए सप्लाई, मेंटनैंस, अपग्रेड और सपोर्ट लगातार मिलता रहे।

ब्रह्मोस दोनों देशों के बदलते रक्षा संबंधों का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और निर्मित यह मिसाइल उस तरह के रक्षा सहयोग का उदाहरण है, जिसे नई दिल्ली ज्यादा से ज्यादा चाहती है, यानी सिर्फ आयातित हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय, संयुक्त विकास, उत्पादन और टैक्नॉलजी पार्टनरशिप उन्नत प्रणालियों और निर्यात के अवसरों में और सहयोग इस मॉडल को और मजबूत कर सकता है।

इसलिए डिफैंस पर हुई बातचीत का महत्व किसी एक नए समझौते की अपेक्षा संबंधों की दिशा से ज्यादा जुड़ा है। भारत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को तेजी से आगे बढ़ाते हुए तकनीक, उत्पादन, रखरखाव और आपूर्ति श्रृंखलाओं में रूस का सहयोग चाहता है। पश्चिमी बाजारों में लगातार पाबंधियों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पांच दिन बैंकिंग की मांग पर 28 से 30 सितम्बर हड़ताल की घोषणा

कोलकाता, 11 सितंबर। पश्चिम बंगाल में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर देश भर में बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। बैंकिंग क्षेत्र की यूनियनों की ओर से सरकार पर पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष शुभ्रज्योति चटर्जी ने कहा कि शुक्रवार की बैंक हड़ताल का मुख्य मुद्दा पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना है। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस मुद्दे को लेकर पहले ही 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर रखी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो 26 अक्टूबर से लगातार हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। उनके अनुसार, बैंक यूनियनों की कई अन्य मांगें भी हैं, लेकिन इस समय पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना सबसे प्रमुख मांग है। सुभ्रज्योति चटर्जी ने दावा किया कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रस्ताव को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है।

- बैंक ऑफिसर्स कॉन्फिडरेशन ने कहा कि यदि समाधान नहीं निकला तो 26 अक्टूबर से लगातार हड़ताल की जायेगी।

सोनम वांगचुक ने आंदोलन पुनः शुरु करने की धमकी दी

वांगचुक ने आरोप लगया कि गृह मंत्रालय के साथ उनके प्रतिनिधियों की कई बार बैठक व बातचीत हुई, पर बैठक की अगली तारीख तय होने के अलावा कोई निर्णय नहीं हुआ है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 सितम्बर। जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने चेतावनी दी है कि अगर केन्द्र सरकार एक सप्ताह के भीतर लद्दाख की लोकतांत्रिक और संवैधानिक मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं देती है, तो 19 से 24 सितंबर, 2026 तक लद्दाख में फिर आंदोलन किया जाएगा। यह चेतावनी 9 सितंबर को नई दिल्ली में लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी), कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के प्रतिनिधियों और गृह मंत्रालय की एक उप-समिति के बीच हुई बैठक के बाद आई है। इस बैठक में अक्टूबर में एक और बैठक तय करने के अलावा कोई खास नई प्रगति नहीं हुई।

ज्ञातव्य है कि वांगचुक ने कई बार भूख हड़ताल का नेतृत्व किया है और सितंबर 2025 में लेह में हुई हिंसा (जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी) के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, वे हिरासत में लिए गए थे। उन्होंने कहा कि हाल की बातचीत में "शायद ही कुछ नया" सामने आया। उन्होंने केन्द्र पर आरोप लगाया कि उसने लेह से कारगिल तक की प्रस्तावित पदयात्रा से ध्यान भटकाने के लिए इस बैठक का इस्तेमाल किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कोई चुनी हुई संस्था नहीं बन जाती, तब तक जमीन, शासन व्यवस्था और स्थानीय संस्थाओं से जुड़े ऐसे फैसलों के खिलाफ आश्वासन नहीं मिलने पर आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, "भरोसा कम हो रहा है और अविश्वास बढ़ रहा है।" उन्होंने आगे भी व्यक्तिगत त्याग के लिए तैयार होने का संकेत दिया है, जिसमें संभावित भूख हड़ताल भी शामिल है। हालांकि, उन्होंने बताया कि वे हाल ही में की गई 26 दिन की भूख हड़ताल से अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं।

अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद, 2019 में लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया था। इससे, जम्मू-कश्मीर से अलग होने की बौद्ध बहुल लेह क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई थी। शुरुआत में इस फैसले का जश्न मनाया गया, लेकिन बाद में लोगों का उत्साह कम हो गया, क्योंकि क्षेत्र की विधायी शक्तियां खत्म हो गईं, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों की शक्तियां कम कर दी गईं और बाहरी लोगों की बढ़ती आमद तथा केन्द्र के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अब विश्वास (ट्रस्ट) घट रहा है तथा अविश्वास बढ़ रहा है।
- अतः वांगचुक 19 सितंबर से 24 सितंबर तक अपना आंदोलन पुनः शुरु करेंगे।
- उन्होंने पुनः अनशन पर बैठने का इरादा भी जताया, हालांकि, उनका शरीर, 26 दिन के अनशन से हुई शारीरिक हानि से अभी पूर्णतया उबरा नहीं है।

ब्रिटिश इकॉनमिस्ट जिम ओनील ने नवंबर 2001 में "ब्रिक" शब्द दिया था विश्व को

उस समय धनाढ्य देशों के संगठन जी7 का एकाधिकार था, ब्रिक का वजूद ना के बराबर था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 सितम्बर। भारत 12 और 13 सितंबर को होने वाले "ब्रिक्स शिखर सम्मेलन" की तैयारी कर रहा है। इस सम्मेलन में 11 सदस्य देशों के नेता शामिल होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उन नेताओं में शामिल हैं, जो नई दिल्ली के "भारत मंडपम" में होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे।

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। राजधानी में करीब 15,000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात किए जाने की उम्मीद है। सम्मेलन के दौरान दिल्ली की ज्यादातर सड़कों को बंद रखा जाएगा।

यह शिखर सम्मेलन यह भी दिखाता है कि 2012 और 2021 में जब भारत ने दिल्ली में सम्मेलन की मेजबानी की थी, उसके बाद से "ब्रिक्स" कितना बदल गया है। चार देशों से शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य हैं, जिससे इसका आर्थिक, जनसंख्या संबंधी और सैन्य प्रभाव काफी बढ़ गया है।

इसी वजह से इसकी तुलना दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संगठन "ग्रुप ऑफ सेवन" (जी7) से भी की जा रही है।

ब्रिक्स की शुरुआत ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के ग्रुप से हुई थी। इन चार देशों ने 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान, "ब्रिक" के रूप में पहली बैठक की थी। पहला

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अब ब्रिक्स का इतना प्रसार हुआ है तथा महत्व बढ़ा है कि उसकी हर स्तर पर जी7 से तुलना होती है और कई क्षेत्रों में ब्रिक्स जी7 को पीछे छोड़ते हुए आगे से आगे निकल गया है, निकलता जा रहा है।

जापान का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता पहुंचा

कोलकाता, 11 सितंबर। भारत और जापान के बीच व्यापार, निवेश तथा सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से जापान के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तापस राय से मुलाकात की। विदेश मामलों के राज्य मंत्री अयानो कुनिमित्सु के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में, राज्य में जापानी निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा और कोलकाता-जापान के बीच हवाई संपर्क बढ़ ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में तापस राय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम बंगाल और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार, कारोबारी सहयोग तथा सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देने के उपायों पर विचार किया।

- प.बंगाल में जापानी निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा तथा कोलकाता -जापान हवाई संपर्क पर चर्चा हुई।

3,000 रूम्स, ब्रिक्स के लिए आरक्षित किए, दिल्ली की होटलों ने

हर होटल में भारी सजावट की गई है तथा उच्च स्तर सुरक्षा भी प्रदान की गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 सितम्बर। 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के आलीशान होटल हाई-सिक्योरिटी वाले कूटनीतिक क्षेत्रों में बदल गए हैं। ब्रिक्स प्रतिनिधियों, साझेदार देशों और वरिष्ठ वैश्विक अधिकारियों के लिए राजधानी के अलग-अलग होटलों में 3,000 से अधिक कमरे बुक किए गए हैं। कुछ आलीशान होटलों में एक रात के कमरे का किराया 2 लाख रुपये से भी अधिक हो गया है।

आइए जानते हैं कि प्रमुख प्रतिनिधिमंडल और अधिकारी कहां ठहरे हुए हैं।

व्लादिमीर पुतिन आईटीसी मौर्य में

सूत्रों के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आईटीसी मौर्य में ठहरे हुए हैं। शिखर सम्मेलन से पहले इस होटल की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और कमरे का किराया फिलहाल 2 लाख रुपये प्रति रात से अधिक हो गया है। पुतिन उन 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं में शामिल हैं, जिनके शिखर सम्मेलन में आने की उम्मीद है।

चीन के राष्ट्रपति ताज पैलेस में

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल भारत पहुंचने की उम्मीद है और वे नई दिल्ली के ताज पैलेस में ठहरेंगे। फिलहाल इस होटल के सभी कमरे बुक हो चुके हैं।

द ओबेरॉय नई दिल्ली

डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग स्थित द ओबेरॉय नई दिल्ली में चार ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के प्रतिनिधिमंडल ठहरे हुए हैं। इनमें ब्राजील, कजाखस्तान, इथियोपिया और इंडोनेशिया शामिल हैं।

होटल, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के आने की भी तैयारी कर रहा है, जिनके दोपहर में होटल पहुंचने की उम्मीद है।

यहां सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से कड़ी है और कई स्तरों पर सुरक्षा जांच की जा रही है।

आम यात्रियों के लिए भी यहां अब बहुत कम कमरे बचे हैं। ओबेरॉय की आधिकारिक वेबसाइट पर फिलहाल होटल पूरी तरह बुक दिख रहा है।

द ताजमहल होटल

द ताजमहल होटल में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों का बड़ा समूह ठहरा हुआ है। उरुग्वे, फिलीपींस, क्यूबा, बेलारूस और वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल इस होटल में ठहरे हैं।

होटल विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक की भी मेजबानी कर रहा है।

द ओबेरॉय की तरह इस होटल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी फिलहाल सभी कमरे बुक दिख रहे हैं।

ले मेरिडियन

ले मेरिडियन नई दिल्ली में ठहरने वाले मेहमानों की सूची ब्रिक्स सरकारों से आगे बढ़कर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस, एशियाई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पुतिन आईटीसी के मौर्य होटल में ठहरे हैं। चीन के राष्ट्रपति ताज पैलेस में रूकेंगे। ओबेरॉय होटल में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ठहरेंगे। ले मेरिडियन में यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंतोनियो गुतारेस के ठहरने की व्यवस्था है।

विमान का इंजन फेल हुआ, दिल्ली में सुरक्षित आपात लैंडिंग

नई दिल्ली, 11 सितंबर। प्रयागराज से नई दिल्ली आ रहे एलायंस एयर के विमान का एक इंजन शुक्रवार दोपहर हवा में फेल हो गया। इसके चलते आईजीआई एयरपोर्ट पर विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार क्रू समेत 40 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।

सूत्रों के मुताबिक, एलायंस एयर की उड़ान संख्या 9आई-698 ने दोपहर प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान, मेरठ के आसपास पायलट को विमान के एक इंजन में तकनीकी दिक्कत महसूस हुई। इसके बाद, पायलट ने स्थिति की जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को दी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत विमान की दोपहर करीब 2:15 बजे आपात लैंडिंग कराई गई।

- प्रयागराज से दिल्ली आ रहे अलायंस एयर के विमान का इंजन हवा में फेल हो गया।

हूथीज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के वैकल्पिक रूट को भी अवरूद्ध करने में सफल होते नज़र आ रहे हैं

इस घटनाक्रम से सऊदी अरब लगभग घुट सा जाएगा

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 सितम्बर। अमेरिका-ईरान युद्ध अब नए क्षेत्रों में फैल रहा है। ईरान के प्राक्सी, यमन के हूती विद्रोहियों ने तेल की आवाजाही के एक महत्वपूर्ण मार्ग पर मौजूद एक अहम द्वीप पर कब्जा कर लिया है और अब बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से गुजरने वाले सभी सऊदी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं।

खबरों के अनुसार, बताया जा रहा है कि उन्होंने यमन के तट पर बाब अल-मंदेब के बेहद करीब स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। इससे हूतियों को ऐसी महत्वपूर्ण जगह मिल गई है, जहां से वे उस जलडमरूमध्य से होने वाली सभी गतिविधियों को खतरे में डाल सकते हैं, जो स्वेज़ और लाल सागर के ट्रैफिक को हिंद महासागर बड़े इलाकों से जोड़ता है।

हूतियों की गतिविधियों ने पहले से ही बढ़े हुए युद्ध के खतरे को और जटिल बना दिया है। ईरान के दर्जनों सैन्य अधिकारी और उसके लिए काम करने वाले लोग पहले से ही हूतियों के कब्जे वाले यमन में मौजूद हैं। वे हूतियों की गतिविधियों को निर्देशित कर रहे हैं, ताकि सऊदी अरब से होने वाली तेल की आवाजाही पर नया नियंत्रण कायम किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी सीएनएन द्वारा उद्धृत कुछ खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी सैन्य ऑपरेटिव बाब अल-मंदेब मार्ग से तेल की आवाजाही को रोकने के लिए इन सैन्य अभियानों में सीधे तौर पर सक्रिय हैं।

बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के समानांतर समुद्री मार्ग है, जो लाल सागर और उत्तर में स्वेज नहर के जरिए एशिया को यूरोप से जोड़ता है और आगे भूमध्य सागर तक पहुंचता है। हूतियों ने अब यमन के तट पर एक बंदरगाह और समुद्री मार्ग के बीच में स्थित एक छोटे से द्वीप पर कब्जा कर लिया है और कहा है कि सभी सऊदी जहाजों पर हमला किया जाएगा।

इससे और भी व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई है। इसका कारण पाकिस्तान का यह हालिया दावा भी है कि पाकिस्तान और तुर्की अब इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि अगर हूती सऊदी जहाजों के खिलाफ अपनी धमकी को लागू करते हैं और किसी सऊदी जहाज पर हमला करते हैं, तो दोनों देश ईरान के समर्थक हूतियों पर हमला करेंगे।

याद दिला दें कि सऊदी अरब ने एक समझौता किया है, जिसे आम तौर पर मक्का समझौता कहा जा रहा है। इसमें, नाटो समझौते की तर्ज पर, यह प्रावधान है कि तीनों में से किसी एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने हाल ही में फिर कहा है कि मक्का समझौते में शामिल देशों को लेकर किसी स्पष्टता की जरूरत नहीं है क्योंकि जिम्मेदारी स्पष्ट है।

अगर पाकिस्तान ईरान के समर्थक हूती लड़ाकों पर हमला करता है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान किस तरह प्रतिक्रिया देगा। चूँकि दोनों देश सीधे पड़ोसी हैं और ऐसी स्थिति में जमीनी संघर्ष भी वास्तविकता बन सकता है।

मक्का समझौते की जिम्मेदारियों के बावजूद, सऊदी अरब पर पहले से छिटपुट रूप से हो रहे हूतियों के हमले ऐसे समय में तेल बाजार में भारी उथल-पुथल पैदा कर सकते हैं, जब बाजार पहले ही संकट में है। तेल की कीमतें पहले ही 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं और इनमें और तेजी आ सकती है।

बाब अल-मंदेब पर खतरा सऊदी अरब के तेल परिवहन के लिए बची हुई एकमात्र जीन रेखा पर खतरा है, क्योंकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य उसके लिए पहले ही बंद है। सऊदी अरब एशिया में अपने खरीदारों तक तेल पहुंचाने के लिए लाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- आशंकाएं-आशंकाएं ही उभर रही हैं।
- क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के समर्थन में उतरेगा, जैसा उसने सऊदी व टर्की के साथ किए सुरक्षा गठबंधन में घोषित किया था।
- पर, क्यों ऐसा करके ईरान से शत्रुता मोल लेगा, क्योंकि, ईरान व पाकिस्तान भी पड़ोसी हैं, सीधी स्पष्ट सीमा है।
- क्या अमेरिका, अब अंततोगत्वा, अपने सैनिकों को सीधे युद्ध में झोंकने को मजबूर होगा।
- क्या ट्रंप अमेरिका में नवंबर में होने वाले चुनाव के पहले यह अलोकप्रिय सा कदम उठाएंगे?

दिल्ली हाईकोर्ट को आठ नये जज मिलेंगे

नई दिल्ली, 11 सितंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय को आठ नये जज मिलेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली में सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने इन जजों की नियुक्ति की अनुशंसा की।

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जज के रूप में नियुक्त करने के लिए तीन महिला न्यायिक अधिकारियों के नाम की सिफारिश की है। कोलीजियम ने गुरविंदर पाल सिंह, निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय शर्मा, संजय शर्मा प्रथम, भरत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज के नाम की अनुशंसा की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 60 है। फिलहाल, दिल्ली उच्च न्यायालय में 44 जज है।

- सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की सिफारिश में तीन महिला न्यायिक अधिकारी शामिल।